

मंहगा हो गया पोहा

300 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़े दाम



इंदौर. इंदौर की थोक सियागंज मंडी में बीते 20 दिनों से पोहे के भाव में इजाफा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि यह बढ़ती स्थाई नहीं है। धान की कमी कम होने और मानसून आने के बाद फिर भाव कम हो जाएंगे। इंदौर पोहा पूरे देश में मशहूर है। इंदौर की होटलों में सबसे ज्यादा पोहे बिकते हैं, जबकि कच्चा पोहा का भी इंदौर में बड़ा मार्केट है। इंदौर और उज्जैन का कच्चा पोहा देशभर में बिकने के लिए जाता है। फिलहाल पोहे की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है और आपूर्ति कम हो रही है। धान की कमी और गर्मी के कारण कारखानों में पोहे का उत्पादन प्रभावित हो गया है। इससे थोक भाव में पोहा 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव बढ़ गए हैं। होटल रेस्त्रां में अभी पोहे की कीमतों में फिलहाल इसका असर नजर नहीं आ रहा है। इंदौर में पोहे 15 से 20 रुपये प्रति प्लेट तक बिक रहे हैं। इंदौर की थोक सियागंज मंडी में बीते 20 दिनों से पोहे के भाव में इजाफा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि यह बढ़ती स्थाई नहीं है। धान की कमी कम होने और मानसून आने के बाद फिर भाव कम हो जाएंगे। फिलहाल इंदौर में पोहा 3400 से 3800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से पोहे बिक रहे हैं। इन दिनों चावल के दामों में भी उछाल है। इसका असर पोहे पर भी पड़ा है। पोहा चावल से ही बनता है। इंदौर में कालीमूँछ, बासमती चावल में भी 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। दरअसल गर्मी में चावल ज्यादा खाया जाता है, जबकि इसका उत्पादन घट जाता है।

इंदौर में सबसे ज्यादा पोहे की खपत

इंदौर में पोहा सबसे पंसदीदा नाश्ता है। आमतौर पर यह सुबह के समय खाया जाता है। शनिवार और रविवार को पोहे की डिमांड ज्यादा रहती है। इंदौर के होटल रेस्त्रां में हर दिन 4 से 5 टन पोहा बिक जाता है। ज्यादातर होटलों में उज्जैन से पोहा मंगाया जाता है। होटल मालिक कच्चे पोहे का स्टॉक करके रखते हैं। इस कारण अभी तैयार पोहे की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है। ज्यादातर होटलों में स्टॉक किया पोहा ही बिक रहा है।

राज्यात टाइम्स

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

साप्ताहिक अखबार

संपादक-गोपाल गावंडे

वर्ष -11/अंक -18/ इंदौर मंगलवार 29 मई से 03 जून-2024/ पृष्ठ-8/ मूल्य-2 रुपए

होशियारपुर में गरजे पीएम मोदी



वोट बैंक की राजनीति ने देश का नुकसान किया

मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। वोट बैंक के प्रति अपने प्यार के कारण देश के बंटवारे के समय करतारपुर साहिब पर अपना अधिकार नहीं जता पाए। यही लोग हैं, जो अपने वोट बैंक के लिए लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे। तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन सीएए का विरोध कर रहा है।

सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं

मोदी ने कहा कि सेना 26 जनवरी में परेड के लिए नहीं दुश्मन से लड़ाई के लिए तैयार की जाती है। मुझे गालियां दो लेकिन देश की सेना का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। रैली में मोदी ने बड़ा एलान किया कि आदमपुर हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने होशियारपुर से भाजपा प्रत्याशी अनीता सोमप्रकाश और आनंदपुर साहिब से सुभाष शर्मा को वोट देने की अपील की।

कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर लिया है

अब आम आदमी पार्टी भी इसमें जुड़ गई है

चंडीगढ़. होशियारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आखिरी चुनावी रैली की। रैली के दौरान मोदी ने अग्निवीर योजना, वाल्मीकि समाज को साधा वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किया।

पंजाब में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी होशियारपुर में पहुंचे। रामलीला ग्राउंड में वे इंडी गठबंधन पर खूब

बरसे। मोदी ने कहा कि मैं अभी चुप बैठा हूँ, जिस दिन मोदी मुंह खोलेंगे तुम्हारी सात पीढ़ी का हिसाब निकाल कर बाहर रख देगा।

मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग मुझे नई-नई गालियां देते हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर लिया है। अब आम आदमी पार्टी भी इसमें जुड़ गई है।

मोदी ने कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने में 70 साल लगे लेकिन आप वाले तो जन्म से ही भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। चुनाव में इन्होंने नशे को लेकर भाषण देकर पंजाब को बदनाम कर दिया और सरकार बनते ही नशे को ही अपनी कमाई का साथी बना लिया।

पंजाब में खेती और उद्योग को बर्बाद कर दिया। नारी उत्पीड़न में भी यह सबसे आगे हैं।

मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले वीरों का अपमान करते हैं। इन्होंने जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था। यह सेना का अपमान था। कांग्रेस राज में सेना को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तेजस फाइटर प्लेन के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वन रैंक वन पेंशन के लिए सवा लाख करोड़ रुपये हमारी सरकार ने खर्च किए। हमारा लक्ष्य भारतीय सेना को सबसे ज्यादा आधुनिक बनाना है।

गुरु रविदास की प्रेरणा से कर रहे काम

पीएम ने कहा कि गरीब कल्याण मेरी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इसमें गुरु रविदास जी की प्रेरणा है। गुरु रविदास जी कहते थे- ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न छोट-बड़ो सब सम बसे, रैदास रहै प्रसन्न। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही अगले 125 दिन में क्या होगा?... इसके रोडमैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए रखे गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।

6 जून के बाद हटेगा तबादलों से प्रतिबंध, कई कलेक्टर-एसपी और अधिकारी हटेंगे

भोपाल. मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री और लगभग पूरा मंत्रिमंडल बदला जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नए होने के कारण बड़ी संख्या में तबादले नहीं किए गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के बाद 6 जून को आचार संहिता समाप्त हो रही है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद जून अंत से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में स्थानांतरण प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि 15 दिन के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने की तैयारी है। विभागों ने तबादलों को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है।

सरकार ने अभी घोषित नहीं की तबादला नीति

चुनावी वर्ष होने के कारण आचार संहिता लागू है, इसलिए राज्य सरकार तबादलों को लेकर नीति की घोषणा नहीं की है। आमतौर पर सरकार तबादलों पर प्रतिबंध हटाने से पहले नई तबादला नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद घोषित करती है, उसी में कितने दिन तबादला होना है और किस स्तर के कर्मचारी-अधिकारी के तबादले का अधिकार अधिकारियों को, जिले के प्रभारी मंत्री को होंगे, इसका भी उल्लेख रहता है। तबादलों से प्रतिबंध हटते ही विभाग सीधे मुख्यमंत्री समन्वय के अनुसार तबादले कर सकेंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण समेत विभिन्न विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जाता है कि नई तबादला नीति में

गंभीर बीमारी, प्रशासनिक, स्वेच्छा सहित अन्य आधार स्थानांतरण को प्राथमिकता मिलेगी।

मानसून सत्र से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी

जानकारी के अनुसार, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने और आचार संहिता हटने के बाद पिछले छह माह से लगा तबादलों पर लगा प्रतिबंध छह जून 2024 को हट जाएगा। इसके बाद विभाग प्रशासकीय आधार पर तबादले कर सकेंगे। वल्लभ भवन में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति जारी नहीं हुई है, लेकिन मानसून सत्र के बाद जारी होने की संभावना है इससे साफ हो जाएगा

कि किस आधार पर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादले होंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति के बाद ही किसी कर्मचारी का तबादला हो सकता है।

दरअसल, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तबादलों पर प्रतिबंध लग गया था। इसके चलते राज्य सरकार चुनाव कार्य में संलग्न 65 हजार बूथ लेवल ऑफिसर, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक समेत कई संवर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले चुनाव आयोग की अनुमति के बाद नहीं कर सकती थी, लेकिन न इस अवधि में केवल उन्हीं अधिकारियों-कर्मचारियों के

तबादले हुए जो प्रशासकीय दृष्टि से बहुत आवश्यक थे।

पसंद के अधिकारियों के लिए जमावट शुरू

प्रदेश सरकार के कई मौजूदा मंत्री ऐसे हैं, जिनका अपने विभाग के प्रमुख सचिवों, सचिवों या अन्य अधिकारियों से पटरी नहीं बैठ पा रही है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें पसंद नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही जिलों में स्थानीय नेताओं से पटरी नहीं बैठाने वाले, शिकायतों या किसी अन्य कारणों से विवादों में आए अधिकारियों को भी बदले जाने की तैयारी है। इसी बीच विधायकगण भी अपने-अपने क्षेत्र के कार्यों को सहजता और प्राथमिकता से कराने के लिए पसंद के अधिकारियों की क्षेत्र में जमावट को लेकर तैयारी कर रहे हैं।



सम्पादकीय

अनावश्यक आयात पर अंकुश लगाया जाए

आज के दौर में कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उसे दूसरे देशों से कुछ न कुछ चीजें आयात करनी ही पड़ती हैं। खासकर विकासशील देशों को कुछ अधिक ही आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा संकेत है कि देश का व्यापार घाटा काफी कम हो गया है। व्यापार घाटा उस अंतर को कहते हैं जो आयात और निर्यात के बीच होता है। जब कोई देश आयात अधिक और निर्यात कम करता है, तो उसका व्यापार घाटा अधिक होता है। अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए आयात और निर्यात में संतुलन जरूरी माना जाता है। पिछले कुछ समय में व्यापार घाटा काफी बढ़ गया था। इस दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में भारत का व्यापार घाटा काफी बढ़ गया था। इसलिए इसे पाटने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा था। अब व्यापार घाटा घट कर 17.43 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में इस व्यापार घाटे में कमी या बढ़ोतरी आयात संबंधी जरूरतों पर निर्भर करेगी। दरअसल, फिलहाल व्यापार घाटे में आई कमी की बड़ी वजह आयात में की गई कमी है। हालांकि अच्छी स्थिति यह मानी जाती है कि देश का निर्यात बढ़ाया जाए। मगर आयात के साथ-साथ निर्यात में भी कमी आई है। बल्कि निर्यात में कमी की दर आयात से अधिक है। आयात में 8.2 फीसद की कमी आई है, तो निर्यात में 8.8 फीसद की। इस लिहाज से इसे बहुत सुखद स्थिति नहीं माना जा सकता। दरअसल, सरकार ने व्यापार घाटा पाटने के लिए राजनीति बनाई कि अनावश्यक आयात पर अंकुश लगाया जाए। जिन वस्तुओं का अपने देश में पर्याप्त उत्पादन होता है, उन्हें बाहर से मंगाने पर रोक लगाई जाए। यही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य भी है। इस लिहाज से आयात किए जाने वाले तीस प्रमुख उत्पादों में से सोलह के आयात में कमी आई है। उनमें सोना, उर्वरक, कच्चा तेल, वनस्पति तेल, रसायन, मोती, मशीनरी तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात में कमी आई है। मगर कोयला, प्लास्टिक की वस्तुओं, लोहा, इस्पात तथा परिवहन उपकरणों का आयात बढ़ा है। मगर इनमें से कितनी वस्तुओं के मामले में लंबे समय तक आत्मनिर्भर रहा जा सकता है, देखने की बात है। निर्यात घटने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि चींकि दुनिया भर में वस्तुओं की मांग घटी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से निर्यात भी घटा है। मगर हमारे यहां निर्यात के संतोषजनक स्तर पर न पहुंच पाने को लेकर चिंता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने से पहले से की जा रही है। फिर जिन स्थितियों का हवाला दिया जा रहा है, उनके जल्दी सुधरने की कोई सुरत भी नजर नहीं आती। इसलिए व्यापार घाटे के रुख में कितना स्थायित्व रह पाएगा, दावा नहीं किया जा सकता। आज के दौर में कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उसे दूसरे देशों से कुछ न कुछ चीजें आयात करनी ही पड़ती हैं। खासकर विकासशील देशों को कुछ अधिक ही आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में रसायनों, कच्चे तेल, वनस्पति तेल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि के मामले में भारत लंबे समय तक आयात पर अंकुश नहीं लगा सकता। दवा निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि के मामले में वह दूसरे देशों पर निर्भर है। इसके बरक्स वह जिन वस्तुओं का उत्पादन अधिक और गुणवत्तापूर्ण करता है, उनका बाजार उसे तलाशना होगा। कोयला, लोहा और इस्पात के मामले में वह उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे सकता है, मगर इनका आयात बढ़ रहा है। निर्यात बढ़ाने के लिए दुनिया में जिस तरह नए बाजार तलाशने और अपनी जगह बढ़ाने के लिए राजनीति बनाने की जरूरत होती है, वह शायद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से निर्यात नहीं बढ़ पा रहा। अगर निर्यात बढ़ेगा, तभी व्यापार घाटे में स्थायी कमी का वातावरण बनेगा।

बरोदिया नोनागिर में पुलिस चौकी खुलेगी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है

हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, ऐसी दुःखद घटना पर राजनीति न हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बरोदिया नोनागिर के पीड़ित परिवार से मिले

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बरोदिया नोनागिर की घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसी घटना न हो, यह हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। यहाँ पर बार-बार घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए यहां पर पुलिस चौकी खोली जाएगी।

क्षेत्र में पुलिस प्रबंधन करते हुए परिवार के बड़े-बूढ़ों को भी विश्वास में लिया जाएगा। जान-माल का नुकसान होना चिंतनीय है। मैं इस अत्यधिक दुःख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ हूँ। घटना के मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है। ऐसी दुःखद घटना पर राजनीति नहीं की जाए।

पीड़ित परिवार को 8 लाख 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मृतक स्व.



राजेंद्र अहिरवार के परिवार को 8 लाख 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आधी राशि 4 लाख 12 हजार 500 रुपये बैंक खाते में जमा होंगे। शेष आधी राशि चालान प्रस्तुत होने पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सागर जिले के खुर्ई तहसील के बरोदिया नोनागिर के पीड़ित अहिरवार परिवार के बीच पहुंचे। विगत दिवस श्री राजेंद्र अहिरवार और उनकी भतीजी

अंजना अहिरवार की हदसे में मृत्यु हो गई थी। डॉ. यादव ने परिवार के बीच बैठकर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री पप्पू रजक के घर जाकर उनके परिवारजनों से भी मुलाकात की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री व विधायक श्री भूपेंद्र सिंह, नरयावली विधायक श्री प्रदीप लारिया, बीना विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे सहित अन्य जनप्रतिनिधि साथ थे।

बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पारितोषिक योजना

भोपाल. मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए पारितोषिक योजना चलाई गई है।

योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संघा/शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाइल पर दे सकता है। हाल ही में कंपनी की वेबसाइट portal.

mpcz.in पर ऑनलाईन सूचना देने की व्यवस्था की गई है। सफल सूचनाकर्ता को अथवा उपभोक्ता को विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि जमा होने पर, बिल की राशि के दस प्रतिशत को पारितोषिक राशि के रूप में दिये जाने की योजना जनवरी 2019 से प्रचलन में है।

योजना के अंतर्गत सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन राशि सीधे संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना में क्षेत्रीय, वृत्त स्तर के अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन शिकायतों पर तत्परता

से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिये कंपनी मुख्यालय के द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जाती है। फर्म, एजेंसी, संगठन भी सूचनाकर्ता हो सकते हैं, जिन्हें कंपनी मुख्यालय में पदस्थ नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है।

पोर्टल अथवा उपाय एप पर देनी होगी सूचना

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना सूचनाकर्ता को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता

को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि कंपनी मुख्यालय द्वारा सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। वर्तमान में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाईन किया गया है तथा कंपनी वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचनाकर्ता के द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उपाय एप के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है।

बगैर जरूरी कारण बिजली आपूर्ति बंद होने पर होगी कार्रवाई-ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

इंदौर. बगैर जरूरी कारण के बिजली आपूर्ति बंद होने पर संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी यह महशूस करें कि अगर इस गर्मी में उनके घर की बिजली एक घण्टे बंद रहेगी तो उनके परिवार को कैसा लगेगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बात मंत्रालय में बिजली ट्रिपिंग और मेंटीनेस की समीक्षा के दौरान कही।

श्री तोमर ने कहा कि कंपनी के संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन यंत्रों से लेकर जूनियर इंजीनियर तक मोहल्ले में उपभोक्ताओं के साथ बैठक कर संवाद करें। उन्हें ट्रिपिंग के कारण बताने के साथ ही बिजली का लोड बढ़वाने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पुरानी केबल के कारण ट्रिपिंग हो रही है, वहाँ के केबल बदलें।

मीटर रीडिंग निर्धारित दिनांक को लें

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हर माह मीटर रीडिंग निर्धारित दिनांक को लें। उन्होंने अनुमानित बिल भेजने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर किसी माह में उपभोक्ता का बिल आश्चर्यजनक ढंग से ज्यादा आता है तो उसका परीक्षण करें।

मेंटीनेस की जानकारी मीडिया में दे

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में बिजली मेंटीनेस किया जा रहा है, उसके दिनांक और समय की जानकारी विभिन्न समाचार माध्यमों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचायें। श्री तोमर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर जनप्रतिनिधियों, किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों से मिलकर ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली, समस्याएं और समाधान से अवगत करायें। फेसबुक, एक्स आदि सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का भी समाधान किया जाये। हर सक्रिय स्तर पर एक टेलीफोन नम्बर शिकायत के लिए रखा जाये। इस पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की मॉनीटरिंग वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाये।

अच्छा कार्य करने वाले को करें पुरस्कृत

श्री तोमर ने कहा कि बिजली कंपनी के किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अच्छा कार्य करने पर उसे पुरस्कृत किया जाये। वसूली आदि के दौरान उनके साथ होने वाली मारपीट की घटनाओं पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं

अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। हर हाल में सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। स्थानीय कारणों से बाधित होने वाली विद्युत आपूर्ति का निराकरण समय-सीमा में करें। बैठक में ओएसडी श्री विजय गौर, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अवैध उत्खनन के 200 प्रकरण दर्ज

अभियान चलाकर जल्ट किए जा रहें डंपर, पोकलेन मशीनें और पनडुब्बियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिए थे अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश

इन्दौर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग पर कार्यवाही जारी है।

नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की जा रही है। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगोन, हरदा एवं शहडोल सहित प्रदेश में लगभग-200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी इत्यादि जल्ट की गयी है और एक करोड़

25 लाख रुपये का राजस्व अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा गत दिवस विभागों की समीक्षा के दौरान, नदियों से अवैध उत्खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 15 जून तक अभियान चला कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन-स्ट्रीम माइनिंग पर प्रभावी रोक लगाने, जितनी मात्रा की ईटीपी जारी की गई है, उससे अधिक परिवहन ना हो यह सुनिश्चित करने और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन ना करना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर और खनिज अधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आंधी, तूफान से टूटे 3 हजार बिजली के पोल बदले

इन्दौर. मई में तीन-चार बार आंधी, तूफान, तेज वर्षा के कारण इंदौर राजस्व संभाग के सभी 8 जिलों में बिजली के सीमेंट पोल टूटने की स्थिति निर्मित हुई। मौसमी कारणों से टूटे गए पोल यथासंभव समय पर बदले गए हैं। मई में इंदौर संभाग के आठों जिलों में तीन हजार पोल बदले गए हैं। इसमें इंदौर जिले के ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्र में 450, खंडवा में 250, खरगोन में 630, झाबुआ में 150, आलीराजपुर में 100, धार में 450, बड़वानी में 490, बुरहानपुर में 480 स्थानों पर सीमेंट के पोल टूटने पर बदलकर विद्युत व्यवस्था समय पर बहाल की गई। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि उक्त कार्य की मानिट्रिंग इंदौर के मुख्य अभियंता श्री एसआर बमनके द्वारा की जा रही है।

संभागायुक्त द्वारा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा

मातृ मृत्यु दर कम करने और एन.आर.सी. को पूरी दक्षता के साथ संचालित करने के लिए निर्देश

इन्दौर. संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने आज इंदौर संभाग के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन की बैठक लेकर निर्देश दिये कि वे अपने जिले में गर्भवती माताओं की मृत्यु दर को कम करना सुनिश्चित करें। उनका गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हो और उन्हें समय रहते बेहतर इलाज मिले ताकि प्रसव के दौरान कोई घटना नहीं हो। संभागायुक्त ने कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए बनाए गए एन.आर.सी. को भी शत प्रतिशत दक्षता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को इलाज के लिए एन.आर.सी. में भर्ती कराने के लिए महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यकर्ता मिलकर कार्य करें। दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा यदि किसी भी जिले में ब्लॉक और जिला स्तर पर संचालित एन.आर.सी. केन्द्र में उपलब्ध बेड खाली रहे, तो दोनों विभागों के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और परिवार नियोजन कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर आर.सी. पनिका सहित सभी जिलों के सीएमएचओ और सिविल सर्जन उपस्थित थे।

नमामि गंगे अभियान से जोड़ें आमजन को-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

5 जून से प्रदेश में शुरू होगा अभियान

नगरों के साथ ही ग्रामों में भी जन सहयोग से सार्वजनिक प्याऊ संचालित किए जाएं

बस स्टॉप आदि पर छांव की व्यवस्था हो, तेज गर्मी से बचाव के उपाय लागू करें

इन्दौर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में एक बैठक में प्रदेश में 5 जून से प्रारंभ हो रहे नमामि गंगे अभियान की तैयारियों के संबंध में अब तक की गई तैयारियों की जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नमामि गंगे अभियान से आमजन को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और जल संरक्षण के

संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पर्यावरण दिवस 5 जून से प्रारंभ हो रहे जल संरक्षण अभियान, जल सम्मेलन आयोजन, जल संरचनाओं के अतिक्रमण हटाने के अभियान और जल स्रोतों को उपयोगी बनाने के कार्यों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा और संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक प्याऊ संचालित हों। पेयजल के कारण कहीं भी समस्या नहीं होना चाहिए। तेज गर्मी से नागरिकों को बचाने के लिए शहर और गांव में आवश्यक शेड और छांव की व्यवस्था की जाए। जहां आवश्यक हो ग्रीन नेट और वाटर स्प्रे के माध्यम से तेज गर्मी से लोगों को राहत दिलवाई जाए। स्थानीय निकाय सक्रिय भूमिका निभायें।

बैठक में बताया गया कि जी आई एस सर्वे के आधार पर प्रदेश के नगरीय निकायों में आवश्यक

सर्वे का कार्य किया गया है। प्रदेश में झील तथा तालाब संरक्षण की 48 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इंदौर में तलावली चांदा तालाब, खुरई में झील संरक्षण, अशोक नगर में जलाशय के संरक्षण कार्यों की व्यापक सराहना हुई है। प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी नगरीय निकायों द्वारा जलाशयों के संरक्षण और उन्नयन के कार्य लगातार हो रहे हैं। नमामि गंगे अभियान के संबंध में सभी जिलों में आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं। जनजागरूकता अभियान के माध्यम से भी गतिविधियों का सक्रिय रूप से संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश जल स्रोतों के स्वच्छता का अभियान संचालित कर जहां आवश्यकता है गहरीकरण के कार्य किए जाएं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अमृत योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करें।

प्रदेश के अनेक स्थानों पर पारम्परिक जल स्रोतों को और जल संरचनाओं के अतिक्रमण हटाए जाएं।

कुएं और बावड़ियों को स्वच्छ बनाने के कार्य हों।



उज्जैन में शनिघाट, भोपाल के छोटे तालाब, इंदौर में लालबाग आदि के निकट जल स्रोतों की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए।

गौवर्धन सागर उज्जैन की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण भी सुनिश्चित किया जाए।

नदियों के विकास की योजनाओं के जानकारी आम जनता को भी दी जाए।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल प्रबंध सुनिश्चित करें, जहां अधिक कठिनाई है वहां टैंकर आदि से जलापूर्ति की जाए। आवश्यक समन्वय कर समाधान निकाला जाए। सार्वजनिक प्याऊ जन सहयोग से प्रारंभ करें।

भूमिगत जल के उपयोग के लिए भी अभियान संचालित किया जाए।

संभागायुक्त द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा

चलित प्रयोगशाला की स्थानीय स्तर पर हो जी.पी.एस. ट्रेकिंग

इन्दौर. संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में इंदौर संभाग के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए।

संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने बैठक में कहा कि विभाग द्वारा संचालित मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला के वाहन की जी.पी.एस. ट्रेकिंग संभागीय मुख्यालय से करें। इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन में बनाए गए कमांड कंट्रोल सेंटर का उपयोग किया जा सकता है। बैठक में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर आर.सी. पनिका, संभागीय



खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनीष स्वामी सहित संभाग के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि इंदौर संभाग में दो मोबाइल प्रयोगशाला चल रही हैं। जिनका मुख्यालय क्रमशः इंदौर एवं खंडवा है। इस चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2021 में 5906, वर्ष 2022 में 6829 तथा वर्ष 2023 में 6979 एवं इस वर्ष आज दिनांक तक 2 हजार 281 नमूने लिए गए हैं।

बैठक में बताया गया है कि

खाद्य निरीक्षकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप निरीक्षण का कार्य किया जाता है। इस वर्ष अभी तक सभी जिलों में कुल मिलाकर लगभग एक हजार 500 निरीक्षण किए जा चुके हैं। निरीक्षण के आधार पर अधिकारियों द्वारा 227 सुधार सूचना पत्र जारी किए गए हैं। अनियमितता पाए जाने पर 40 लाइसेंस निरस्त भी किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इंदौर में पाँच और खरगोन में एक एफ.आइ.आर. भी दर्ज कराई गई है। विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खराब क्रिस्म की

खाद्य सामग्री की जल्ती भी की गई है।

इस विभाग के अधिकारियों द्वारा अधिनियम के तहत प्रकरण बनाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान में संभाग के सभी जिलों में कुल मिलाकर 274 प्रकरण ए.डी.एम. कोर्ट में और 43 प्रकरण सी.जी.एम.कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।

बैठक में श्री मनीष स्वामी ने बताया कि शासन द्वारा ईट राइट कैम्पेन चलाया जा रहा है, जिसमें इंदौर देश में प्रथम स्थान पर भी आ चुका है। इस वर्ष के कैम्पेन के परिणामों की घोषणा आगामी जून माह में की जाएगी, जिसमें इंदौर की रैंकिंग पुनः अच्छी आने की संभावना है।

संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खाद्य कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस के लिए विशेष शिविर भी लगाए।

सहज योग कैसे करें, जानिए उसके फायदे

सहजयोग का चमत्कार

सहज योगा को धार्मिक योगा की श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि आसान मुद्रा में बैठकर ध्यान करना सहज योगा कहलाता है। इस योग के दौरान ठंडी हवा का एहसास होता है। आत्म बोध का प्रचार है जिससे कुंडलिनी होती है। सहज योगा हाल ही में खोजा गया एक धार्मिक योगा है। इसकी खोज निर्मला श्रीवास्तव ने की जो 'श्री माता जी निर्मला देवी' के नाम से भी जानी जाती हैं। उनके अनुयाईयों ने प्यार से (जिन्हें सहज योगी कहते हैं) उन्हें 'माता' का नाम दिया है। सहज योगा में कुंडलिनी जागरण व निर्विचार समाधि, मानसिक शांति से लोगों को आत्मबोध होता है और अपने आप को जानने में मदद मिलती है।

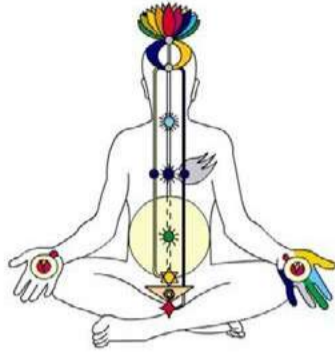
यथा है सहज योगा

सहज योगा में आसान मुद्रा में बैठकर ध्यान किया जाता है। ध्यान के दौरान इसका अभ्यास करने वाले लोगों में सिर से लेकर हाथों तक में एक ठंडी हवा का एहसास होता है। चिकित्सकों ने सहज योगा के अन्य

प्रभावों के बारे में भी बताया है। इस योग को करने से लोगों में शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्ति व आराम मिलता है। सहज योगा केवल एक क्रिया का नाम नहीं है, यह वह तकनीक भी है जिससे लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया गया है। यह मुख्य रूप से आत्म बोध का प्रचार है जिससे कुंडलिनी जागृत होती है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है।

सहज शब्द की उत्पत्ति

सहज शब्द संस्कृत के दो शब्दों को जोड़ कर बना है। 'सह' का अर्थ है 'साथ' और 'जा' का अर्थ है 'जन्म'। जब यह दोनों शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसका अर्थ है प्राकृत के करीब होना। सहज योगा के अनुयाईयों का विश्वास है कि उनके अंदर कुंडलिनी का जन्म होता है और वे उन्हें स्वतः जागृत कर सकते हैं।



जानें सहज योगा से होने वाले फायदे

सामान्य स्वास्थ्य के लिए सहज योगा से शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से मजबूती मिलती है। साथ ही शरीर में होने वाली बीमारियों को जड़ को खत्म किया जा सकता है।

तनाव से मुक्ति

सहज योगा से दिमाग को तनाव झेलने की शक्ति मिलती है। साथ ही आपके सोने के तरीके को भी सुधारता है। इस योगा से व्यक्ति को आसपास के तनाव, दिनभर की थकान व अपने गुस्से को नियंत्रित करने में आसानी होती है।

बुरी आदतों से छुटकारा

किसी भी तरह की बुरी आदत व लत से जैसे धूम्रपान, मंदिरा सेवन आदि को छोड़ने के लिए इसका अभ्यास किया जा सकता है।

संचार कौशल

सहज योगा के नियमित अभ्यास से आप लोगों से अच्छी तरह से पेश आते हैं। साथ ही दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते जोड़ने में मदद मिलती है।

एकाग्रता

सहज योगा से लोगों में एकाग्रता बढ़ती है और जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं।



इंदौर. ख्यात पर्यावरणविद् डॉ. सुनील चतुर्वेदी ने चेताया और कहा कि सतपुड़ा के घने जंगल जिस तरह से कट रहे हैं और नर्मदा क्षेत्र के आसपास जिस तरह से बांधों के निर्माण हो रहे हैं, उसके चलते जीवनदायिनी नदी नर्मदा दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में इंदौर को नर्मदा का पानी अधिकतम 30 वर्ष और मिल सकता है। इसके बाद नदी बहुत हद तक सूख जाएगी। अतः हम आज से ही वर्षा के जल को सहेजें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।

डॉ. चतुर्वेदी आज श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति सभागृह में अभ्यास मंडल के मंच पर मुख्य वक्ता के बतौर बोल रहे थे। जलवायु परिवर्तन के दौर में जल संरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व

विषय पर बोलते हुए आगे कहा कि जल ही जीवन है और हम सब जल पर निर्भर हैं। बीते कुछ वर्षों से जल संकट बढ़ता जा रहा है। नदियां सूखकर नाले में तब्दील हो रही हैं। कुएं और बावड़ियां कम होते जा रही हैं। पोखर और तालाब भी या तो सूख चुके हैं अथवा उन पर अतिक्रमण हो गया है। ऐसे में केवल वर्षा का पानी ही अब हमारे जल का बड़ा स्रोत रह गया है। जल की कमी का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम जितना पानी जमीन से निकाल रहे हैं उतना सहेज नहीं रहे हैं। अतः यह संकट प्रकृति प्रदत्त कम और मानव प्रदत्त अधिक है।

घर की छत से डेढ़ लाख लीटर पानी संरक्षित होगा

डॉ. चतुर्वेदी ने आगे कहा कि वर्षा के जल का संरक्षण कर हम एक बड़े संकट से बच सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि छतों पर एकत्रित हुए जल को हम पाइप के सहारे जमीन में उतारे। एक अनुमान के मुताबिक वर्षा ऋतु में 1500



चेतावनी 30 साल में सूख जाएगी नर्मदा

वर्ग फीट की छत पर करीब डेढ़ लाख लीटर पानी एकत्रित होता है जिसमें से अधिकांश बह जाता है। वर्षा के जल को सहेजने का एक तरीका जमीन में चार बाय चार फीट का गड्ढा खोदें और उसमें नीचे तक पाइप डालें। इन दोनों तरकीबों से भू जल स्तर बढ़ेगा। वर्षा जल से भूजल स्तर को बढ़ाते समय अधिक सावधानी की भी जरूरत है, क्योंकि अगर भूमि पर कार्बन, प्लास्टिक या

और कोई अपशिष्ट है तो वह भी वर्षा जल के साथ भूमि में जाएगा, जो रोग का कारण बनेगा। पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होगी तो कैंसर का खतरा और यदि फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई तो हड्डियों का कमजोर होना तय है। अतः जिस जल को हम जीवन कहते हैं, वह कभी कभी किलर भी बन जाता है। तीसरा तरीका छत के ऊपर हजार दो हजार लीटर की पानी की टंकी रखें और

उसमें वर्षा का जल एकत्रित कर उसे घरेलू कार्यों में उपयोग करें।

अतिथियों को स्वागत में तुलसी के पौधे दिए

मंच पर अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता और सचिव माला ठाकुर भी उपस्थित थे। अशोक कोठारी, स्वप्निल व्यास, एनके उपाध्याय, हबीब बेग आदि ने अतिथियों का स्वागत तुलसी के पौधे से किया। अतिथियों को प्रतीक चिन्ह पर्यावरणविद् एसएल गर्ग और वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा ने प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन वैशाली खरे ने किया और आभार माना सुनील व्यास ने। कार्यक्रम में पर्यावरणविद् ओपी जोशी, शंकर गर्ग, ओम नरेड़ा, नेताजी मोहिते, संजय गुप्ता, शरद कटारिया, दशरथ गोलाने, अनिल भोजे, किशन सोमानी, फादर लकारा, कुणाल भंवर, ग्रीष्मा त्रिवेदी, दीप्ति गौर आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मांस-मछली के अवैध विक्रय पर तीसरे दिन भी हुई कार्यवाही

भोपाल. प्रदेश के सभी नगरीय निकायों द्वारा खुले में मांस-मछली बेचने और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले मांस-मछली विक्रेताओं के विरुद्ध रोजाना मौके पर ही कार्रवाहियां की जा रही है।

तीसरे दिन मंगलवार को प्रदेश के 16 नगर निगमों, 99 नगर पालिकाओं और 298 नगर परिषदों सहित सभी 413 नगरीय निकायों में कुल 111 विक्रय केन्द्रों

पर कार्रवाई की गई। नगरीय निकायों द्वारा संबंधितों पर कार्रवाई कर 41 हजार 350 रुपये का अर्थदंड भी वसूला गया। सर्वाधिक 23 हजार 500 रुपए का अर्थदंड भोपाल संभाग के नगरीय निकायों द्वारा वसूला गया। नगर निगम भोपाल द्वारा नगर निगम की परिधि में नियम विरुद्ध संचालित की जा रही मांस-मछली विक्रय की दुकानों पर सघन कार्यवाही की जा रही है।

भोपाल शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में मंगलवार को 63 दुकानों पर अर्थदंड की कार्यवाही की गयी।

इसी तरह नगर निगम, इंदौर के निगरानी दल द्वारा भी नियमित रूप से शहर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है तथा मांस-मछली खुले में न बिकें, इस नियम का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मंगलवार को नियम विरुद्ध संचालित दुकानों से खण्डवा में 7 किलो और सागर में 20 किलो मांस जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी संभागों में भी बड़े पैमाने पर मांस-मछली के अवैध विक्रय पर विधिनुरूप कार्रवाईयों की गईं।

मंगलवार को 41 हजार 350 रुपये अर्थदंड वसूला गया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छिन्दवाड़ा की दुःखद घटना पर शोक व्यक्त किया छिन्दवाड़ा की घटना से प्रभावित पीड़ित परिवार को मिलेगी पूर्ण सहायता- मुख्यमंत्री

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिन्दवाड़ा में एक युवक द्वारा परिवार के 8 लोगों की हत्या कर स्वयं आत्महत्या करने की हृदय विदारक घटना पर गहन शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूँ।

राज्य सरकार द्वारा पीड़ित परिवार की पूर्ण सहायता की जाएगी। उन्होंने मृतक परिवार को दस लाख रुपए और घायल बालक के इलाज के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घटना की जाँच के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उईके आज छिन्दवाड़ा पहुंचीं और उन्होंने घटनास्थल ग्राम बोदल कछार पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। मंत्री श्रीमती उईके ने प्रभावित परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी।

अपर मुख्य सचिव श्री विनोद कुमार, आई.जी. श्री अनिल कुशावाहा, डी.आई.जी. श्री सचिन अतुलकर, जबलपुर संभाग के आयुक्त श्री अभय कुमार वर्मा, कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि इस हादसे में परिवार की दो बहनें बच गई हैं, जो विवाहित थीं और अपने ससुराल में थीं। मृतकों की अंत्येष्टि के लिए 10-10 हजार की राशि और तत्कालीन सहायता के तौर पर 50-50 हजार रुपए और घायल के तत्काल इलाज के लिए 50 हजार की सहायता राशि के चेक पीएचई मंत्री श्रीमती उईके ने पीड़ित परिवार की बहनों को सौंपे। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। उल्लेखनीय है कि छिन्दवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक के बोदल कछार गांव में कल रात एक युवक ने अपने परिवार के 8 सदस्यों की हत्या करके खुद फांसी लगा ली थी। प्रारंभिक जाँच में आरोपी मृतक युवक मानसिक रूप से विकसित बताया गया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का दावा-

महागठबंधन की सरकार बनेगी, मप्र में जीतेंगे 10 से 12 सीट

खंडवा. कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 10 से 12 सीटें हम जीत रहे हैं। चार जून को जो नतीजे आएंगे वे इंडि गठबंधन के पक्ष में होंगे। वहीं, यादव ने पीएम मोदी पर अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया।

मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव देर शाम खंडवा पहुंचे। इस दौरान वे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अहमद पटेल के यहां आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने समर्थकों से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की, जिसमें वे आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने परिणामों को कांग्रेस और सहयोगी इंडि गठबंधन के फेवर में आने की बात कही। साथ ही इंडि गठबंधन की सरकार बनाने का दावा भी किया। इस दौरान कांग्रेस नेता अरुण यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तीखा हमला किया। यादव ने कहा कि जब उनकी और उनकी



पार्टी की स्थिति खराब होती है तो वे अनर्गल बयान देते हैं।

प्रधानमंत्री करते हैं अनर्गल बयान बाजी

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष यादव ने कहा कि मैं समझता हूँ कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वे पूर्ण रूप से इंडि गठबंधन के समर्थन में आएंगे। हम अच्छे बहुमत से देश में सरकार बनाएंगे।

मध्य प्रदेश में जहां तक हमारा आंकलन है, 10 से 12 सीट कांग्रेस के पक्ष में आएंगी। भाजपा के बनाए राम मंदिर के चुनावी मुद्दे के माहौल को लेकर उन्होंने कहा कि अब यह तो 4 तारीख को तय होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि नतीजा महागठबंधन के पक्ष में आएगा। इंडिया गठबंधन के हर साल प्रधानमंत्री बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब यह तो प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं। उनकी और उनकी पार्टी की स्थिति कैसी है वो खुद जान रहे हैं और जब उनकी स्थिति खराब होती है तो प्रधानमंत्री जी अनर्गल बयान बाजी करते हैं।



Your Exclusive Summer Haven in Our
Farm Houses!

OFFERED AT

399/- Sqft

BOOK NOW

8889066688
8889066681

अक्सर कई लोगों की यह शिकायत रहती है कि जब वे दूध पीते हैं, तो उसे पचा नहीं पाते हैं. यह परेशानी किसी भी उम्र के लोगों के साथ हो सकती है.

जब ऐसे लोग दूध या दूध से बने उत्पादों का सेवन करते हैं, तो उन्हें पेट में दर्द, पेट फूलना या उल्टी-दस्त की समस्या होने लगती है. इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं.

सोनाली सिद्धार्थ सावंत, अरिस्टेट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, (फूड टेक्नोलॉजी), शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर

लैक्टोज दूध और दूध से बने उत्पादों में पाया जाने वाला नेचुरल शुगर है. जब किसी व्यक्ति को दूध हजम नहीं हो पाता, तो उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होती है. एलर्जी के अलावा डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं. एक आंकड़े के मुताबिक, देशभर में लैक्टोज इंटॉलरेंस से 3 से 4 फीसदी बच्चे और एक फीसदी वयस्क पीड़ित हैं.

व्या है लैक्टोज इंटॉलरेंस

यह शरीर में लैक्टोज एंजाइम की कमी की वजह से होता है. जब छोटी आंत में दूध का लैक्टोज पहुंचता है, तो सिक्रिटेड (स्रावित) लैक्टोज एंजाइम से ग्लूकोज और गैलेक्टोज टूट जाता है, इससे दूध पचाना आसान होता है. वहीं, जब इस एंजाइम की कमी होती है, तो लैक्टोज टूट नहीं पाता. ऐसे में दूध पचना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस स्थिति को ही 'लैक्टोज इंटॉलरेंस' कहा जाता है. मां के दूध को पचाने के लिए लैक्टोज की बेहद जरूरत होती है. अधिकतर बच्चों के शरीर में जन्म के समय इसकी मात्रा ज्यादा होती है. कई कारणों से जब बच्चों में इस एंजाइम की मात्रा कम हो जाती है, तो उनके लिए मां का दूध पचना कठिन हो जाता है.

लैक्टोज इंटॉलरेंस का निदान और उपचार

अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं. डॉक्टर आपके खान-पान की आदतों और लक्षणों के साथ कब से यह समस्या है, इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं. इसे डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर बॉडी टेस्ट की भी सलाह दे सकते हैं जैसे- हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, मिल्क टोलेरेन्स टेस्ट, स्माल बॉवेल बायोप्सी टेस्ट आदि. इन जांचों के आधार पर डॉक्टर इलाज शुरू कर सकते हैं. लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए लैक्टोज युक्त खाद्य पदार्थों को कम करके या उनसे बिल्कुल परहेज करके भी इस स्थिति का इलाज किया जा सकता है. जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की दिक्कत होती है, उन्हें खान-पान के जरिये कैल्शियम की पूर्ति करने की सलाह दी जाती है.

दूध उत्पादों से है परेशानी तो खान-पान में बदलाव जरूरी



लैक्टोज इंटॉलरेंस को ऐसे पहचानें :

- दस्त और गैस बनना
- जी मिचलाना और उल्टी
- पेट में सूजन और ऐंठन
- मसल्स और जोड़ों का दर्द
- पेशाब करने में परेशानी
- कंसट्रेशन में कमी

इनमें भी होता है लैक्टोज

- कुकीज, केक और बिस्कुट
- सूप, ब्रेड और बेक्डफूड
- कैंडी स्वीट्स व प्रोसेस्ड फूड

डेयरी प्रोडक्ट्स की बजाय इन चीजों का करें सेवन

दूध को कैल्शियम का सबसे बेहतरीन स्रोत माना जाता है. अगर आपको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है, तो आप इन खाद्य पदार्थों का सेवन कर शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं.

चिया सीड्स : कैल्शियम की

कमी पूरा करने के लिए चिया सीड्स भी एक अच्छा विकल्प है. महज दो बड़े चम्मच चिया सीड्स के भीतर 179 मिलीग्राम कैल्शियम होता है. स्मूदी, सलाद या ओट्स के ऊपर डालकर इसे खा सकते हैं.



टोफू : टोफू भी एक सोया

उत्पाद ही है. महज आधा कप टोफू में 126 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है. यह आपकी रोजाना की खुराक का लगभग 86 प्रतिशत होता है. टोफू में सभी तरह के अमीनो एसिड पाये जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं.



सूरजमुखी के बीज :

सनपलावर सीड्स के अंदर प्रोटीन, गुड फैट, और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाये जाते हैं, जो आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने का काम करते हैं. महज एक कप सनपलावर सीड्स के अंदर 109 मिलीग्राम कैल्शियम भी पाया जाता है, जो आपकी रोजाना की खुराक को कुछ हद तक पूरी कर सकता है. इससे आप काफी सक्रिय रहेंगे.



सोया मिल्क : डेयरी उत्पादों

का सबसे बड़ा विकल्प सोया मिल्क है. इसके अंदर आपको एक सर्विंग पर करीब 500 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है. यह प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत है, जो मसल्स बिल्ड करने में मददगार साबित होता है. **ओट्स** : जिन लोगों को कैल्शियम की जरूरत को पूरा करना है, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है. एक कप



बीन्स : बीन्स को कैल्शियम का पावर हाउस भी कहा जाता है. एक कप बीन्स में 191 मिलीग्राम से ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है. आप सूप के अंदर या अन्य सब्जियों के साथ बीन्स का सेवन कर सकते हैं.

ओट्स के अंदर लगभग 200 मिलीग्राम कैल्शियम होता है. यह आपकी दिनभर की खुराक कुछ हिस्सा आसानी से पूरा कर देता है.



स्त्री रोग

पीसीओएस से लड़ने के लिए जीवनशैली में लाएं ये पांच बदलाव

बदलती जीवनशैली और खान-पान की गलत आदतों की वजह से लोग कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की चपेट में आ रहे हैं. पीसीओएस और पीसीओडी भी इन्हीं समस्याओं में से एक है. खराब जीवनशैली की वजह से आजकल कई महिलाएं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज (पीसीओएस) की चपेट में आ रही हैं. यह एक ऐसी बीमारी होती है, जिसमें महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं. इसमें महिलाओं के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफी ज्यादा बढ़ने लगता है. इसका स्वास्थ्य पर भी काफी विपरीत असर दिखता है. अपनी जीवनशैली में ये पांच बदलाव लाकर इस समस्या से काफी हद तक काबू पा सकती हैं.



गहरी सांस लें :

रोजाना गहरी सांस लेने से तनाव कम होता है. इससे शरीर को आराम और बेहतर नींद में मदद मिल सकती है. सही ढंग से सांस लेना व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है. इसके फायदे बेशुमार हैं. इससे रक्त प्रवाह में सुधार, एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी, पाचन क्रिया दुरुस्त रहता है.



खान-पान सही रखें :

अगर आपको पीसीओएस की समस्या है, तो सबसे पहले अपने खान-पान में बदलाव करें. सही समय पर नाश्ता और भोजन करें. अपनी डाइट में हेल्दी प्रोटीन और फैट जरूर शामिल करें. खाने में घर का बना पौष्टिक, पौधे आधारित और पानी से भरपूर आहार लें. साथ ही बॉडी डिटॉक्स करने के लिए नियमित रूप से भाप लें. वहीं, कोशिश करें कि कैफीन से दूर रहें. कैफीन का नियमित सेवन ब्लड प्रेशर के स्तर को प्रभावित कर सकता है.



पर्याप्त नींद लें :

जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो आपके शरीर में उच्च गुणवत्ता वाले हार्मोन्स बनते हैं, जिससे पीसीओएस से राहत मिल सकती है. वहीं, पर्याप्त नींद लेने से आप ब्लड प्रेशर, हाइ कोलेस्ट्रॉल आदि समस्या से भी बच सकते हैं.



रोजाना व्यायाम व योग करें :

रोजाना एक्सरसाइज और योग करने से न केवल पीसीओएस की समस्या से निजात मिलेगी, बल्कि शरीर भी चुस्त-दुरुस्त रहेगा. इसलिए अपना काम जहां तक हो सके खुद करें. वॉक पर जाएं, लोगों से मिलें.



तनावमुक्त रहें :

पीसीओएस से जुझ रही महिलाओं को तनाव से दूर रहना चाहिए. अक्सर महिलाएं कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हैं. इस चलते बेवजह तनाव ले ले लेती हैं. हालांकि, कई बार फसटेशन होने लगती है, लेकिन आपकी हेल्थ और पॉजिटिविटी से आप इस समस्या को कम कर सकती हैं.

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर नदी, तालाब, कुआँ, बावड़ी तथा अन्य जल स्रोतों के संरक्षण हेतु विशेष अभियान

कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा जारी किये गये व्यापक निर्देश

इन्दौर. कलेक्टर श्री आशीष सिंहने जिलेके समस्त नगरीय निकायों को स्थित विभिन्न जल स्रोतों, नदी, तालाबों, कुआँ, बावड़ियों तथा अन्य जल स्रोतों का अविरल बनाये जाने के लिए संरक्षण एवं पुर्नजीवन के कार्य करने के निर्देश दिये है।

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर 5 जून से 15 जून तक जिले के समस्त नगरीय निकायों में प्रवाहित होने वाली तालाबों एवं जल संरचनाओं के पुर्नजीवीकरण/संरक्षण का विशेष अभियान चलाया जायेगा। उक्त अभियान हेतु शहरी क्षेत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग नोडल

विभाग होगा।

नगरीय निकायों द्वारा भारत सरकार की अमृत 2.0 योजनान्तर्गत जल संरचनाओं के उन्नयन का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस विशेष अभियान के अंतर्गत सामाजिक तथा अशासकीय संस्थाओं एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत जन अभियान परिषद की सहभागिता सुनिश्चित कराई गई है।

अमृत 2.0 योजनान्तर्गत प्रचलित जल संरचनाओं के उन्नयन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस अभियान में पूर्ण कराया जायेगा। अमृत 2.0 योजना अंतर्गत नगरीय निकाय में चयनित जल संरचनाओं के अतिरिक्त यदि कोई नदी, झील, तालाब, कुआँ, बावड़ी इत्यादि उपलब्ध है और इनका पुर्नजीवीकरण/संरक्षण की आवश्यकता है, तो इन संरचनाओं का उन्नयन कार्य स्थानीय, सामाजिक, अशासकीय संस्थाओं एवं जनभागीदारी के माध्यम से कराया जाये। जल

संरचनाओं में मिलने वाले गंदे पानी के नाले/नालियों को स्वच्छ भारत मिशन (SBM 2.0) अंतर्गत क्रियान्वित लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के माध्यम से डायवर्सन के उपरांत शोधित कर जल संरचनाओं में छोड़ा जाये। जल संरचनाओं के चयन के साथ-साथ इनके जीर्णोद्धार तथा नवीनीकरण के परिणाम संयोजित (Outcome linked) उद्देश्य जैसे- जलप्रदाय, पर्यटन, भू-जल संरक्षण, मत्स्य पालन, सिंचाई का उत्पादन इत्यादि का स्पष्ट निर्धारण किया जाये। जल संरचनाओं के चयन एवं उन्नयन कार्य में जी.आई.एस. तकनीक का उपयोग तथा नगरीय निकाय द्वारा स्थल पर जाकर चिन्हित संरचना की मोबाइल एप के माध्यम से जियो टैगिंग की जाये।

जल संरक्षण के जीर्णोद्धार/उन्नयन कार्य में कैचमेन्ट के अतिक्रमण को हटाना। कैचमेन्ट के उपचार जैसे- नाले/नालियों की सफाई अथवा इनका डायवर्सन, सिल्ट ट्रेप, वृक्षारोपण, स्टार्म वाटर

ड्रेनेज मैनेजमेन्ट इत्यादि, बंद विस्तार, वेस्ट वियर सुधार अथवा निर्माण, जल भराव क्षेत्र में जमा मिट्टी अथवा गाद को निकालना, डि-वीडिंग, एरेशन, पिचिंग/घाट निर्माण, इत्यादि कार्य किये जायें। जल संग्रहण संरचनाओं से निकाली गई मिट्टी एवं गाद का उपयोग स्थानीय कृषकों के खेतों में किया जाये। जल संरचनाओं के किनारों पर यथासंभव बफर जोन तैयार किया जाये। इस जोन में हरित क्षेत्र/पार्क का विकास किया जाये। जल संरचनाओं के किनारों पर अतिक्रमण को रोकने के लिये फेंसिंग के रूप में वृक्षारोपण किया जाये तथा इनके संरक्षण के लिये सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाये। जल संरचनाओं के आस-पास किसी भी प्रकार सूखा अथवा गीला कचरा फेंकना प्रतिबंधित किया जाये। प्रतिबंधित गतिविधियों हेतु सूचना पट्टी लगाई जाये। निकाय अंतर्गत पुराने कुएं एवं बावड़ियों की साफ-सफाई/मरम्मत कार्य इस अवधि में

सम्पन्न कराई जाये। निकाय क्षेत्र अंतर्गत विद्यमान रिहायशी रैन वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम यदि बंद पड़े है, तो उनकी सफाई कराकर उन्हें पुनः उपयोग किये जाने हेतु जागरूक किया जाये। जल संरचनाओं के जल की गुणवत्ता (Physical, Chemical & Biological Parameters) की जांच कराई जाये। जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार/नवीनीकरण कार्य के क्रियान्वयन के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निकाय के तकनीकी अमले, संभागीय कार्यालय एवं

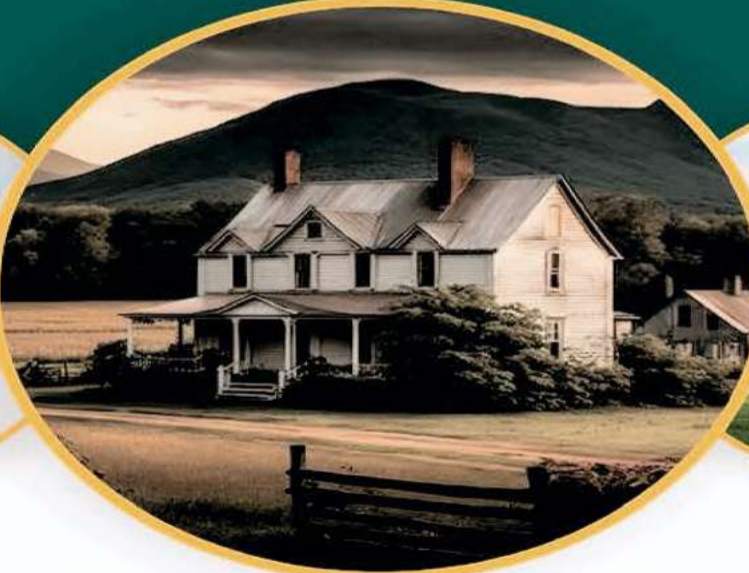
तकनीकी सलाहकारों के द्वारा सतत मॉनीटरिंग की जाये। जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार/उन्नयन उपरांत वाटर ऑडिट (संरचना की क्षमता वृद्धि क बाद कितना पानी संग्रहित हुआ, कितना वितरित हुआ अथवा उपयोग हुआ तथा क्या परिणाम और लाभ प्राप्त हुये) के आधार पर निर्मित संरचना के अपेक्षित परिणाम (Expected Outcome) के अनुक्रम में प्राप्त हुए वास्तविक परिणामों (Achieved Outcome) का विश्लेषण और सत्यापन कराया जाये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान में आयोजित विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अभूतपूर्व प्रदर्शन कर 17 पदक जीतने पर बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह सम्पूर्ण भारत के लिए गौरवमयी ऐतिहासिक क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का विश्व पैरा-एथलेटिक्स में 34वें स्थान से 6वां स्थान प्राप्त करना भारतीय खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प एवं कठिन परिश्रम को दर्शाता है।



INVEST YOUR SAVING IN TO BIG RETURN



399/- SQFT

इंदौर - इच्छापुर नेशनल हाईवे से 400 मी. की दुरी पर।



8889066688, 8889066681



उज्जैन में 15 और 16 जून को क्षिप्रा परिक्रमा, गंगा दशमी से जुड़ेंगे नागरिक पवित्र क्षिप्रा नदी को की जायेगी चुनरी अर्पित-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में आगामी 15 एवं 16 जून को नवमी एवं दशमी पर क्षिप्रा परिक्रमा के कार्यक्रम होंगे। रामघाट से यात्रा प्रारंभ होगी जो दत्त अखाड़ा, त्रिवेणी, गढ़ कालिका और गोमती कुंड जैसे पवित्र स्थलों से निकलेगी। आम जन द्वारा पवित्र क्षिप्रा नदी को चुनरी अर्पित की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम जन शामिल होते इसलिये यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रम पारंपारिक उल्लास के साथ संपन्न हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज मंत्रालय में हुई बैठक में क्षिप्रा परिक्रमा, गंगा दशमी कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 16 जून की शाम रामघाट, दत्त अखाड़ा क्षेत्र में होने वाले सांस्कृतिक आयोजन के स्वरूप की जानकारी प्राप्त की। यह कार्यक्रम महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ तरफ से होगा। इस अवसर पर क्षिप्रा नदी के महत्व और उसके सांस्कृतिक वैभव की जानकारी देने वाली विशेष पुस्तिका का लोकार्पण भी होगा। सदानारा केंद्रित ऑडियो-वीडियो सीडी का लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्षिप्रा परिक्रमा, गंगा दशमी कार्यक्रम के गरिमामय आयोजन के साथ ही प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों जैसे नर्मदा जी, चंबल, ताप्ती, सोन, सिंध और बेनगंगा आदि के तट पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और जलक्रीड़ा गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए। इसके साथ ही नदियों के किनारे स्थित देव स्थलों की सफाई और मंदिर परिसर की स्वच्छता के

कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गत बीस वर्ष से क्षिप्रा परिक्रमा, गंगा दशमी का आयोजन हो रहा है जिसमें समाज का प्रबुद्ध वर्ग, आम नागरिक और इतिहास पुरातत्व के विद्वान भी शामिल होते हैं। यह सामाजिक समरसता का प्रतीक पर्व भी है। भजनों की प्रस्तुति और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम इसकी विशेषता है। इस समृद्ध परंपरा को पूरे प्रदेश में विस्तारित करते हुए नागरिकों की भागीदारी से अन्य नदियों के घाटों पर भी आयोजन करने की कल्पना को साकार किया जाए।

बैठक में ऐतिहासिक एवं पारंपरिक जल संरचना के संरक्षण संवर्धन पर अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी एवं विकास और जल संसाधन विभाग, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

विभाग, आयुक्त उज्जैन संभाग तथा न्यासी सचिव वीर भारत न्यास के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण एवं जिला उज्जैन के सामाजिक कार्यकर्ता ऑनलाइन जुड़े।

बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला और निदेशक महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ श्री श्रीराम तिवारी ने क्षिप्रा परिक्रमा की तैयारियों पर प्रजेंटेशन दिया।

जल संरक्षण का लोकव्यापी अभियान चलेगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन के निकट पवित्र क्षिप्रा सहित प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों और तालाबों तथा जल संरचनाओं के संरक्षण पर निरंतर कार्य पर जोर दिया और जल संरक्षण के लिए लोकव्यापी

अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश की लगभग 212 नदियों, जल संरचनाओं और जो पारंपरिक जलस्रोत रहे हैं (वर्तमान में विलुप्त हो चले हैं) सभी की सैटेलाइट मैपिंग करवा कर प्राचीन वांगमय, परंपरा, के संदर्भों के साथ सर्वे आधारित डाक्यूमेंटेशन विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद तथा वीर भारत न्यास का प्रकाशन किया जाएगा। पूरे राज्य में नदियों के आसपास मंदिरों, पुरासम्पदा, जलीय जीवों के जीर्णोद्धार संरक्षण की दिशा में पहल की जाएगी। गंगा दशमी पर पारंपरिक क्षिप्रा परिक्रमा को अब बड़े स्तर पर संयोजित किया जायेगा। आगामी वर्ष, वर्ष प्रतिपदा से जो सृष्टि के निर्माण का दिन है तथा उज्जैन गौरव दिवस भी और विक्रम संवत् का प्रथम दिन भी है, इस तिथि से उज्जैन सहित पूरे मध्यप्रदेश में जल संरक्षण का लोक व्यापी अभियान चलाया जाएगा।

रेत उत्खनन में अवैध रूप से लगी मशीनों को तत्काल जप्त किया जाए-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रेत उत्खनन नियमानुसार हो, उत्खनन में अवैध रूप से लगाई गई मशीनों को तत्काल जप्त किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में हुए निर्णयों के पालन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार, श्री जे.एन.कंसोेटिया, श्री राजेश राजौरा श्री मनु श्रीवास्तव, श्री अजीत केसरी, श्री मलय श्रीवास्तव, श्री के.सी. गुप्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक चार माह में प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएं। उन्होंने उज्जैन में हुई समिट के बाद जबलपुर प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप हुए विकास कार्यों तथा अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियों पर केंद्रित संभाग स्तरीय बुकलेट प्रकाशित कराई जाए। बैठक में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम्, रीवा और उज्जैन संभाग की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियावयन पर चर्चा हुई।

आम आदमी को राहत और विकास को गति देगा जिलों और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आम आदमी को राहत, प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को गति देने, जनसामान्य की समस्याओं को कम करने, प्रशासनिक और विभागीय दक्षता व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तहसील, विकासखंड, जिलों और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है। इस प्रक्रिया में जन भावनाओं और जनप्रतिनिधियों के विचारों को अवश्य शामिल किया जाए। दूरस्थ ग्रामों को निकटतम जिला मुख्यालयों से जोड़ने, पुलिस कमिश्नरेंट व जिला कलेक्टर की व्यवस्था में समन्वय, बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम के प्रस्तावित क्रियान्वयन को भी इस प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाए।

प्रत्येक जिले में स्टेडियम विकसित हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं समय-सीमा में पूर्ण हों, इस उद्देश्य से राज्य सरकार के विभाग रेलवे को हर संभव सहयोग प्रदान करें। प्रदेश में नए रेल रूट विकसित करने के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों को बड़े शहरों से जोड़ने, परस्पर दूरी कम करने व तेज गति से विकास के लिए नए एक्सप्रेस-वे की कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महाविद्यालयों के समायोजन की आवश्यकता है, जहां मांग हो और पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध हों, वहीं महाविद्यालय संचालित किए जाएं।

सूने मकानो मे चोरी करने वाले नकबजन, 24 घंटे के अंदर तिलक नगर पुलिस की गिरफ्त मे

वारदात में चोरी गया एक लेपटॉप, हार्ड डिस्क, स्मार्ट वाच, व आभूषण सहित पूरा माल बरामद।

आरोपियों ने महं से एक्टिवा चोरी कर, उसी गाड़ी से दिया था थाना तिलक नगर क्षेत्र मे घटना को अंजाम

इंदौर। शहर मे अपराधों पर नियंत्रण हेतु चोरी, नकबजनी, लूट आदि संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इनमें लिप्त बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के तारतम्य में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना तिलक नगर द्वारा चोरी की घटना का 24 पर्दाफाश कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।

पुलिस थाना तिलक नगर पर दिनांक 26.05.2024 को फरियादी शशांक पहाडिया पिता संजय पहाडिया निवासी जी- 1 साई छाया अपार्टमेंट 84 महादेव तोतला नगर इंदौर ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 25.05.2024 को वह और उसकी पत्नी दोनो आफिस चले गये थे। शाम को करीबन 7.30 बजे घर आये तो घर का दरवाजा टुटा हुआ तथा घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। फरियादी

की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 454,380 भा.द.वि का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया।

क्षेत्र में चोरी, नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस आयुक्त जोन 02 श्री अभिनव विश्वकर्मा व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन - 02 अमरेंद्र सिंह के दिशा निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त खजराना श्री कुंदन मण्डलोई द्वारा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई।

पुलिस टीम द्वारा तुरत कार्यवाही करते हुए मुखबिर तंत्र की सूचना एवं पूछताछ के आधार पर आरोपी 1.दीपक शाही नि- रेवेन्यु नगर इंदौर वर्तमान पता - ज्ञानशीला सिंगापुर टाऊनशीप इंदौर एवं 2. आरिफ बेग निवासी जल्ला कालोनी, इंदौर को विधिवत गिरफ्तार किया।

पूछताछ में पता चला कि आरोपियों द्वारा घटना मे उपयोग एक्टिवा क्रमांक MP-09-SU-4813 को घटना से तीन दिन पहले महं से की थी चोरी उसके बाद दिनांक 25.05.2024 को थाना तिलक नगर क्षेत्र मे उसी एक्टिवा से की थी नकबजनी की वारदात। आरोपियों से चोरी गया मश्रूका एक लेपटॉप, हार्ड डिस्क, स्मार्ट वाच, व आभूषण सहित घटना मे प्रयुक्त एक्टिवा भी जप्त की गई है।

दोनों आरोपी आदतन अपराधी है जिनमे आरोपी दीपक शाही के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, चोरी, अवैध शराब व अवैध हथियार आदि विभिन्न धाराओं के 06 अपराध तथा आरोपी आरिफ बेग के विरुद्ध चोरी, नकबजनी, अवैध शराब, जुआ एक्ट व अवैध हथियार आदि विभिन्न धाराओं के 11 अपराध, शहर के विभिन्न



थानों में पंजीबद्ध है।

पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। तथा आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।

उक्त सराहनीय कार्य को करने मे थाना प्रभारी तिलक नगर अजय कुमार नायर, उ.नि. महेन्द्र सिंह दण्डोतिया, सउनि संजय सिंह चौहान, प्र.आर 3016 मुजफ्फर, आर. 3592 पप्पु रघुवंशी एवं आर.524 विकास की अहम भूमिका रही।